

रिपोर्ट करने योग्य

सर्वोच्च न्यायालय, भारत

2023 दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल आवेदन संख्या 521-522

(2017 के एसएलपी (सी) संख्या 14948-14949 से उत्पन्न

एलुमलाई @वेंकटेशन और अन्य

.....अपिलार्थ

बनाम

एम. कमला और अन्य. और ईटीसी.

..विपक्षगण

निर्णय

के. एम. जोसेफ, जे.

1. अनुमति दी गई ।
2. श्री सेंगलानी चेट्टियार का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। उक्त विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था श्री चंद्रन अपीलार्थी । अपीलार्थी श्री चंद्रन के पुत्र हैं। ने एक बार फिर से श्रीमती. कुप्पम्मल के साथ शादी की। दूसरी शादी से सेंगलानी चेट्टियार के पाँच पुत्रियाँ व एक पुत्र था । इस मुकदमे में विवाद ए-अनुसूची सम्पति से संबंधित है, जो कि सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से पैदा हुए छ बच्चों में से दो बच्चों द्वारा दायर किया गया है । सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से 6 बच्चों में से दो बच्चों द्वारा विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया गया है । विवादित सम्पति श्री सेंगलानी चेट्टियार की स्व-अर्जित सम्पति थी। उक्त सम्पति के संबंध में,

अपीलार्थियों के पिता चंद्रन ने एक रिहाई विलेख निष्पादित किया था । रिहाई विलेख दिनांकित 12.11.1975, की शर्तें इस प्रकार हैं:-

15:26:53 IST

इस जारी किए गए विमोचन विलेख को सेंगलानी चेट्टियार के पक्ष में 12 नवंबर, 1975 को निष्पादित किया जाता है। सी. सेंगलानी चेट्टियार, पुत्र सिंगारा चेट्टियार, संख्या 144, वेंकटचाला मुदाली स्ट्रीट मीरसापेट, मायलापुर, चेन्नई में रहता है। 2. सेंगलानी चेट्टियार, लगभग 2 साल की उम्र के अपने नाबालिग बेटे, विनयगर्नूर्ति के संरक्षक के रूप में, सेंगलानी चेट्टियार के बेटे, एस चेट्टियार द्वारा निष्पादित यह विलेख, जो 19, सांता साहिब स्ट्रीट, मीरसापेट, मायलापुर, चेन्नई में रहता है, इस प्रकार है:

मैं आपकी पहली पत्नी का बेटा हूँ। चूंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे बंधक सोने के आभूषणों के हस्तांतरण के माध्यम द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसकी कीमत रु। 10,000/- और मूल्य की सामग्री 5,000/- और मानामथी गाँव में स्थित आवास स्थलों के संबंध में मेरे हिस्से को जारी करना, जो इस दिन इस दस्तावेज के माध्यम द्वारा हमारा है और विशेष रूप द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है। उपरोक्त आवास स्थल की तुलना विरुद्ध Rs.10,500/- की बंधक राशि का निपटान आपके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हमारा उक्त संबंध के अलावा कोई अन्य संबंध नहीं है। इस तरह से मैंने इस मुक्ति विलेख को निष्पादित किया था।

3. जैसा कि भाग्य में होगा, श्री चंद्रन का निधन 09.12.1978 पर हुआ। सेंगलानी चेट्टियार की मृत्यु 19.01.1988 पर हुई। सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी पत्नी, श्रीमती. कुप्पम्मल ने

25.08.2005 पर अंतिम सांस ली। मूल वाद संख्या 8173 का 2006

उमा रवि चंद्रन और विनयगा मूर्ति द्वारा दायर किया गया था, जो पहले से ही देखे गए थे, कि सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से उनके बच्चे थे। प्रतिवादी 1 से 3 सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से अन्य बेटियाँ थीं। अपीलार्थियों को बाद में प्रतिवादी 4 और 5 के रूप में आरोपित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 को इस तरह से आरोपित किया गया और वह सेंगलानी चेट्टियार की दूसरी शादी से हुई मृत बेटी का बेटा है।

4. अपीलार्थियों को बाहर करने का वादी का मामला उनके द्वारा निष्पादित रिहाई विलेख पर आधारित था जो कि अपीलार्थियों के पिता ने निष्पादित की थी । यद्यपि यह पाया गया है कि रिहाई विलेख अपीलार्थियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए एक बाधा नहीं होगी कारण यह है कि चंद्रन ने रिहाई विलेख 1975 में निष्पादित किया जब उसके पिता सेंगलानी चेट्टियार जीवित थे । यह पाया गया कि रिहाई विलेख अपीलार्थियों के लिए अपने दादा सेंगलानी चेट्टियार कि सम्पत्ति पर उत्तराधिकार पाने में बाधा नहीं होगी । वादी मात्र 2/7 हिस्सा प्राप्त करने के योग्य पाए गए। तदनुसार वादी को अन्य बातों के साथ-साथ 2/7 हिस्सेदारी का फरमान दिया गया था। जहां तक 'बी' अनुसूची सम्पत्ति का संबंध है, मुकदमा खारिज कर दिया गया। वादी ने 2009 का ए. एस. संख्या 883 दाखिल किया। प्रतिवादी 1,3 और 6 ने 2009 का ए. एस.

संख्या 718 दायर किया। विवादित फैसले से उच्च न्यायालय ने इन अपीलों को स्वीकार कर लिया है और पाया है कि अपीलार्थी मृतक सेंगलानी चेट्टियार की सम्पत्ति में किसी भी हिस्से का दावा करने के हकदार नहीं थे। निचली विचारण न्यायालय की डिक्री को पलटने का मूलभूत आधार इस विचारण न्यायालय द्वारा गुलाम अब्बास बनाम हाजी कयाम अली और अन्य में निर्धारित आदेश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संक्षेप में, आधार यह है कि जहां तक श्री चंद्रन ने अपने पिता से विचार प्राप्त करने के बाद रिहाई के विलेख को निष्पादित किया, अपीलकर्ता ए-अनुसूची सम्पत्ति में एक हिस्से पर दावा करने से वंचित हो जाएंगे। अदालत ने दूसरे अभियोक्ता की मृत्यु पर भी ध्यान दिया और पाया कि पहली अभियोक्ता और उसके भाई-बहन अर्थात् प्रतिअभियोक्ता 1 से 3 अकेले दूसरे अभियोक्ता के हिस्से के उत्तराधिकारी होंगे। दूसरे शब्दों में, यह पता लगाने के पश्चात कि अभियोक्ता डी1 से डी3 और डी6 ए-अनुसूची सम्पत्ति में प्रत्येक के छठे हिस्से के हकदार होंगे और दूसरे अभियोक्ता की मृत्यु को देखते हुए, पहले अभियोक्ता और प्रतिवादियों 1 से 3 को 5/24 हिस्सा मिलता पाया गया और छठे प्रतिअभियोक्ता को 4/24 हिस्सा मिलना था । ए-अनुसूची सम्पत्ति में हिस्सेदारी से इनकार करने से व्यथित महसूस कर रहे हैं कि प्रतिवादी 4 और 5 इस न्यायालय के समक्ष हैं।

1 ए. आई. आर 1973 एस. सी. 554

5. श्री सिद्धार्थ अय्यर, अपीलार्थियों के विद्वान वकील, श्री उमाशंकर, विद्वान अधिवक्ता प्रथम अभियोक्ता की ओर से विद्वान वकील और श्री जयंत मुथ राज, प्रतिअभियोक्ता संख्या 2 और 6 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अय्यर तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय ने गलती की गुलाम अब्बास (ऊपर) से समर्थन प्राप्त करना। वह इंगित करेंगे कि मामला मुस्लिम कानून के से उत्पन्न हुआ और उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धान्त का उपयोग अपीलार्थियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के रूप में उनके हिस्खंड से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वह, वास्तव में, इंगित करेगा कि 1975 में पहला अपीलकर्ता मुश्किल से तीन साल का था जब रिहाई विलेख निष्पादित किया गया था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि दूसरे अपीलकर्ता का जन्म भी नहीं हुआ था। सम्पत्ति अपीलार्थियों के दादा की अलग सम्पत्ति है और अपीलार्थी खंडंगलानी चेट्टियार के पूर्व-मृत बेटे के

बेटे हैं, धारा 8 से, कानून अपीलार्थियों को हिस्खंडदारी देता है। सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की खंड 6 का संदर्भ दिया गया है। वे बताते हैं कि 1975 में जब रिहाई विलेख निष्पादित किया गया था, अपीलकर्ता के पिता श्री चंद्रन के पास केवल एक विशेष उत्तराधिकार था। भविष्य में सफल होने की केवल उम्मीद एक वैध स्थानांतरण का विषय नहीं बन सकती है। इसलिए, निचली विचारण न्यायालय रिलीज डीड को अमान्य दस्तावेज के रूप में नजरअंदाज करने में पूरी तरह से सही है। दूसरे शब्दों में, जब वर्ष 1988 में खंडंगलानी चेट्टियार प्रश्न सम्पत्ति का उत्तराधिकार खोला गया, तो विचाराधीन सम्पत्ति खंडंगलानी चेट्टियार के नाम पर थी और धारा 8 के संदर्भ में, पूछताछ के आधार पर अपीलकर्ताओं के वैध हिस्खंड के उत्तराधिकारी होने का अधिकार नहीं हो सकता है। यह भी बताते हैं कि उच्च न्यायालय ने हिंदू अल्पसंख्यक की खंड 8 का अधिदेश और संरक्षकता अधिनियम, 1956 को नजरअंदाज किया। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थियों के पिता श्री चंद्रन को शायद अपने पिता के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करने के रूप में माना

जा सकता है। यद्यपि समझौता खंड 8 को देखते हुए अपीलार्थियों को बांधने के लिए काम नहीं कर सका। वह अग्रेतर प्रस्तुत करेगा कि अपीलकर्ताओं के दादा को वसीयत निष्पादित करने या अन्यथा सम्पति से निपटने से कुछ भी नहीं रोकता था। वह श्री चंद्रन की निर्वसीयत मृत्यु के परिणाम से अवगत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपीलार्थियों को सम्पति पर उत्तराधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिए कानून को कोई सुरक्षा नहीं दी। 1978 में उनके पिता श्री चंद्रन और 1988 में दादा की मृत्यु की तारीखों के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि सम्पति हस्तांतरण अधिनियम की खंड 43 के अर्थ के भीतर अनुदान देने के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

7. श्री जयंत मुथ राज, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपीलार्थियों का समर्थन करते हैं। वह स्वीकार करता है कि अपीलार्थियों के लिए समर्थन एक बाद का विकास है। दूसरे शब्दों में, मूल रूप से, श्री जयंत मुथ राज के ग्राहक, जिनमें से एक सेंगलानी चेट्टियार की बेटियों में से एक है और दूसरा श्री बाबू, छठा प्रतिवादी (सेंगलानी चेट्टियार की पूर्व-मृत बेटी

के बेटे) ने अपीलार्थियों के दावे का विरोध किया था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जयंत मुथ राज के मुवक्किलों के पक्ष में अपीलार्थियों के हिस्से के संबंध में बाद में एक कार्य सौंपा गया है। जाहिर तौर पर, यह उनके मुवक्किलों के रुख में अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिवर्तन को स्पष्ट करता है। श्री जयंत मुथ राज तर्क देंगे कि गुलाब अब्बास (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के *फैसले में* उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए तथ्य शामिल थे जिनके आधार पर रोक का सिद्धान्त लागू किया गया था। हालाँकि, तत्काल मामले के तथ्य बहिष्कार के सिद्धान्त यद्यपि पुष्टि नहीं करते थे। वह तर्क देंगे कि गुलाम अब्बास के मामले में, इस न्यायालय द्वारा सह-उत्तराधिकारियों के आचरण को ध्यान में रखा गया था ताकि यह माना जा सके कि वे बहिष्कृत हैं। दूसरी ओर, इस मामले में वह तर्क देंगे कि एक स्पष्ट विरोधाभास था। अपीलार्थियों के लिए कोई आचरण जिम्मेदार नहीं है। सेंगलानी चेट्टियार के बच्चों ने सह-उत्तराधिकारियों के आचरण के आधार पर बहिष्कार के सिद्धान्त के आधार पर मामला नहीं बनाया है जैसा कि गुलाम अब्बास (ऊपर) मामले में स्थिति थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रश्न के संबंध में यह पूछे

जाने पर कि क्या यदि निष्कासन श्री चंद्रन को लागू करता है, तो अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी (पूर्व-मृत बेटे की संतान होने के नाते) के रूप में उनके अधिकार से वंचित करने के लिए यह लागू किया जा सकता है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि इसमें शामिल सम्पत्ति सेंगलानी चेट्टियार की एक अलग सम्पत्ति थी। वह दृढ़ता से तर्क देंगे कि गुलाम अब्बास (ऊपर) के सिद्धान्त को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया था। श्री जयंत मुथ राज तर्क देंगे कि यह अदालत इस बात पर ध्यान दे सकती है कि दादा ने सम्पत्ति का सौदा नहीं किया था और यह दर्शाता है कि वह चाहते थे कि सम्पत्ति का उत्तराधिकार, उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 8 के जनादेश के अनुसार हो।

8. इसके विपरीत, श्री उमाशंकर, प्रथम अभियोक्ता और दूसरे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। विद्वान वकील ने रिहाई विलेख की शर्तों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अदालत को पक्षों की मंशा को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी शादी में सेंगलानी चेट्टियार को एक बेटा हुआ। वह

मानसिक रूप से ठीक नहीं था। पार्टियाँ बटे के हितों की रक्षा करना चाहती थीं। यह बताता है कि क्यों रिलीज विलेख का निष्पादन अपीलार्थियों के दादा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पुत्र के पक्ष में किया जाता है। यह इंगित करने के अलावा कि श्री चंद्रन ने विचार प्राप्त किया है और अपने सभी अधिकारों को छोड़ दिया है, यह अपीलार्थियों के मुंह में नहीं होगा कि वे सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए दावा करें।

विश्लेषण

9. प्रश्नगत सम्पत्ति सेंगलानी चेट्टियार की अलग सम्पत्ति पाई गई है ।

1988 में उनकी मृत्यु हो गई। सेंगलानी चेट्टियार ने दो बार शादी की थी।

उनकी पहली शादी से श्री चंद्रन का जन्म हुआ था। श्री चंद्रन का वर्ष 1978

में अपने पिता से पहले निधन हो गया था। पूर्व-मृत पुत्र की संतान होने के

नाते, अपीलकर्ताओं को आम तौर पर इस मामले में निचली विचारण

न्यायालय द्वारा तय किए गए हिस्से को विरासत में मिला होगा। विमोचन

विलेख की शर्तों में कहा गया है कि श्री चंद्रन ने सम्पत्ति के संबंध में अपना

हिस्सा जारी कर दिया है। यह भी स्पष्ट है कि श्री चंद्रन द्वारा किया गया

त्याग उनके बहुमूल्य सम्मान प्राप्त करने पर आधारित था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज ने यह तर्क देने का प्रयास कि रिहाई विलेख सम्पत्ति के बारे में है जो "हम" से संबंधित है । कुछ भी एक जैसा नहीं होता और हम हैं दोनों अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आधार पर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है कि सम्पत्ति श्री सेंगलानी चेट्टियार की स्व-अर्जित सम्पत्ति थी।

10. सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 में ऐसी सम्पत्ति की गणना की गई है जिससे हस्तांतरित किया जा सकता है। यह घोषणा करता है कि सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। खंड 6 (ए) घोषणा करती है कि किसी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अवसर, किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर विरासत प्राप्त करने के संबंध का अवसर या समान प्रकृति की अन्य केवल संभावना को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। समान रूप से, एक व्यक्ति जो उत्तराधिकारी बन सकता है और अपने रिश्तेदार की मृत्यु पर कानून के सफल होने का हकदार है, उसे तब तक कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि संपत्ति का

उत्तराधिकार नहीं खोला जाता है। जब श्री चंद्रन के पिता श्री सेंगलानी चेट्टायर जीवित थे, तब उनके बेटे श्री चंद्रन के पास विशेष उत्तराधिकारी थे। एक सह-भागीदार के विपरीत, जो केवल अपने जन्म से संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त करता है, हिंदू की अलग सम्पत्ति के संबंध में, ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि रिहाई विलेख का अपने आप में श्री चंद्रन के अधिकारों के हस्तांतरण का प्रभाव उसके पिता या उसके पिता के नाबालिग बेटे के पक्ष में दूसरी शादी से नहीं हो सकता है।

11. जो देखना को बाकी है वह यह है कि क्या आचरण मुक्ति विलेख को निष्पादित करने में श्री चंद्रन की भूमिका और मुक्ति विलेख को निष्पादित करने के लिए विचार प्राप्त करना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप रोक का निर्माण होगा। मामले की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए, संक्षेप में, क्या यह एक ऐसा मामला है जहां न्यायसंगत बहिष्कार का सिद्धांत श्री चंद्रन को दावा करने से रोकता यदि वह अपने पिता से बच जाते। जहाँ तक अपीलार्थियों के दावे का संबंध है, श्री चंद्रन के विरुद्ध बहिष्कार के अस्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है यदि ऐसा बहिष्कार किया जाता है? अग्रेतर प्रश्न यह होगा कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 8 का क्या प्रभाव होगा ।

12. इससे पहले कि हम विवादों से निपटने के लिए आगे बढ़ें, इसके

तथ्यों पर करीब से नज़र डालना आवश्यक है गुलाम अब्बास (ऊपर) का मामला और उसमें क्या निर्धारित किया गया है। उक्त मामले में शामिल तथ्य इस प्रकार थे: -

निम्नलिखित है:

उस मामले में, एक मुसलमान की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे 5 बेटे, एक बेटी और एक विधवा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गया। उनके तीन बेटों ने जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया । उनके पिता पर कर्ज था। उस समय, जब उनके पिता अपने ऋण के परिणामस्वरूप सम्पत्ति से पूरी तरह से वंचित होने की संभावना को देख रहे थे, तो उनके दो बेटे आगे आए और उन्होंने ऋण चुकाया। हालाँकि यह मूल्य के साथ आया था । उसके दो बेटों, अर्थात् अभियोक्ता और चौथे प्रतिअभियोक्ता ने विलेखों में सम्पत्ति में भविष्य में किसी भी अधिकार का दावा नहीं करने के लिए कुछ नकद और चल सम्पत्ति की प्राप्ति को स्वीकार किया। इस संबंध में प्रासंगिक शब्द इस प्रकार हैं:

"मैंने उपरोक्त चीजों को अपने हिस्से के बराबर के रूप में लिया है और मैंने इसे स्वतंत्र रूप से लिखा है। इसके बाद की संपत्तियों पर मेरा कोई दावा नहीं है और अगर मैं भविष्य में किसी भी संपत्ति पर दावा करता हूं तो इस दस्तावेज़ से मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मुझे अपने पिता द्वारा मेरे अन्य भाइयों को कोई भी संपत्ति देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।"

13. इस अदालत ने ए. आई. आर. 1976 इलाहाबाद 573 में इलाहाबाद

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी।

अदालत ने पाया कि:

"उचित सम्मान के साथ, हम मद्रास उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण खंड से सहमत होने में असमर्थ हैं कि एक प्रत्याशित का त्याग, एक कथित लेकिन कानूनी रूप खंड अप्रभावी हस्तांतरण के रूप में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा मारा जाता है। चूंकि यह हस्तांतरण के रूप में शून्य होगा, इसलिए अनुबंध अधिनियम की धारा 23 पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि सम्पत्ति का कोई "हस्तांतरण" नहीं था, जो सही स्थिति थी, लेकिन एक साधारण अनुबंध था, जो मात्र भविष्य में ही काम कर सकता था, तो निश्चित रूप से इसका उद्देश्य तत्काल हस्तांतरण करना नहीं था, जो कि मुस्लिम कानून के शासन द्वारा अमान्य कर दिया गया था। वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या किसी हस्तांतरण या अनुबंध के अलावा, कथित त्याग और मूल्यवान प्रतिफल की प्राप्ति के कार्यों में घोषणाएं कई वर्षों तक संचालित होने वाले पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, जिसने समग्र रूप से, सम्पत्ति के अधिकार के सफल दावे के विरुद्ध एक अवरोध पैदा किया जब वह अधिकार वास्तव में अस्तित्व में आया। एक न्यायसंगत अवरोध, यदि इसके तत्व स्थापित किए जाते हैं, तो उन अधिकारों के दावे को रोकने वाले साक्ष्य के नियम के रूप में काम करता है जो अन्यथा मौजूद हो सकते हैं।

7. सर रोलैंड विल्सन ने अपने "एंग्लो मोहम्मदन लॉ" (पृष्ठ 260, पैरा 208) में इस स्थिति को इस प्रकार बताया है:

"उन पाठकों के लिए जो हिंदू कानून के सबसे व्यापक रूप से प्रचलित स्कूल के अनुसार पिता और पुत्र के संयुक्त स्वामित्व से परिचित हैं, शायद यह स्पष्ट रूप से कहना वांछनीय है कि रोमन

और अंग्रेजी कानून की तरह मुसलमान में भी यही है। एक जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। एक प्रत्यक्ष या अनुमानित उत्तराधिकारी का ऐसा कोई प्रत्यावर्ती हित नहीं होता है जो उसे कब्जे में मालिक द्वारा की गई किसी भी बिक्री या उपहार पर आपत्ति करने में सक्षम बनाता है; अब्दुल वहीद, एल. पी. 12 आई. ए., 91, और 11 कैल 597 (1885) देखें। जिसके बाद हसन अली, 11 ऑल 456, (1889) में आया। इसके विपरीत भी सच है: मैं एक प्रत्याशित उत्तराधिकारी द्वारा त्याग उसके पूर्वज का जीवनकाल वैध नहीं है, या विरासत के निहित होने के पश्चात उसके विरुद्ध लागू करने योग्य नहीं है।"

जहाँ तक इसकी बात है, यह कानून का एक सही कथन है, क्योंकि उत्तराधिकार की अपेक्षा का केवल त्याग भविष्य में प्रत्याशित उत्तराधिकारी के आचरण को बाध्य नहीं कर सकता है। लेकिन, यदि प्रत्याशित उत्तराधिकारी अग्रेतर बढ़ता है और प्रतिफल प्राप्त करता है और खुद को इस तरह से संचालित करता है कि वह किसी मालिक को अपनी सम्पत्ति का निपटान न करने के लिए गुमराह करे, तो प्रत्याशित उत्तराधिकारी को अपना अधिकार स्थापित करने से रोका जा सकता है जब वह निर्विवाद रूप से उस पर निहित होता है। दूसरे शब्दों में, इस कथन से अवरोध का सिद्धान्त अछूता है।"

(महत्व दिया गया)

14. सम्पत्ति, यानी 'ए' अनुसूची, श्री चंद्रन थी पैतृक सम्पत्ति नहीं थी । श्री चंद्रन ने इस पर अधिकार मात्र प्राप्त किया होता जब उनके पिता की

निर्वसीयत मृत्यु हो गई होती। इस प्रकार, वह मात्र एक स्पष्ट उत्तराधिकारी था। एक उत्तराधिकारी द्वारा स्थानान्तरण, जो स्पष्ट रूप से केवल विशेष का उत्तराधिकारी है, किसी भी अधिकार को व्यक्त करने के लिए अप्रभावी है। केवल रिहाई विलेख के निष्पादन से, दूसरे शब्दों में, इस मामले के तथ्यों में, कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ। यह सरल कारण है कि स्थानान्तरण अर्थात् अपीलार्थियों के पिता को ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिसे वह स्थानान्तरित कर सके या त्याग सके। यद्यपि अगर उसका आचरण ऐसा था कि उसे भगा दिया जा सकता था तो रिहाई विलेख का निष्पादन उसके अधिकार को खतरे में डाल देगा और इसलिए अपीलार्थियों के दावे पर भी एक अपरिवर्तनीय छाया डाल देगा जब तक कि हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ अय्यर की अन्य प्रस्तुतियों में योग्यता नहीं पाते।

15. अपीलार्थियों और श्री जयंत मुथ राज का तर्क है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता के दादा ने रिहाई विलेख पर कार्रवाई की और यह कि उसने रिहाई विलेख के आधार पर कोई विलेख निष्पादित नहीं किया, यह हमें अपील नहीं करता है। श्री सेंगलानी चेट्टियार ने दो बार शादी की। पहले संघ ने अपीलार्थियों के पिता को प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने फिर से शादी कर ली। यह दूसरी शादी और उक्त विवाह से बच्चों के जन्म के पश्चात है कि रिहाई विलेख 12 नवंबर, 1975 को निष्पादित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी शादी से एक बेटा पैदा हुआ था जो संयोग से

बीमार था और जिसके पक्ष में अपीलार्थियों के पिता ने रिहाई विलेख को निष्पादित किया। सेंगलानी चेट्टियार का इरादा दूसरी शादी से बेटे के हित को सुरक्षित करना प्रतीत होता है। वह अपने हित को सुरक्षित करना चाहता था दूसरी शादी से और जिसके लिए अपीलार्थी का पिता जो प्रथम विवाह से उनके पुत्र थे, उन्हें कुछ मूल्यवान विचार दिया गया, जिसने श्री चंद्रन को विचाराधीन सम्पत्ति के संबंध में अपने सभी अधिकारों को जारी करने के लिए राजी प्रश्न या। 'रिहाई विलेख' के शब्द कि इसके बाद उनका रक्त संबंध के अलावा कोई अन्य संबंध नहीं था, यह दर्शाता है कि श्री चेट्टियार का इरादा सम्पत्ति के संबंध में श्री चंद्रन पर किसी भी दावे से इनकार करना था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगर गुलाम अब्बास (उपरोक्त) के सिद्धान्त को लागू किया जाता और श्री चंद्रन ने अपने पिता का पूर्व निधन नहीं किया होता, तो सब कुछ पक्षों की योजना के अनुसार होता।

16. हमारा मानना है कि यह अनुमान लगाते हुए कि श्री चंद्रन अपने पिता और उनके उत्तराधिकार से बच गए हैं अपने पिता की संपत्ति के संबंध में निर्वसीयत, रिहाई विलेख को निष्पादित करने के आचरण के परिणामस्वरूप भले ही अपने आप में एक वैध हस्तांतरण न हुआ हो, लेकिन उनके आचरण के साथ विचार की प्राप्ति के कारण श्री चंद्रन को छोड़ दिया गया होगा। यह तथ्य कि श्री चेट्टियार ने वसीयत के माध्यम से किसी भी दस्तावेज़ को निष्पादित नहीं

किया, मात्र यह दर्शाता है कि वे इस आधार पर आगे बढ़े कि शाखा का प्रतिनिधित्व श्री चेट्टियार ने किया था जो चंद्रन को विरासत कि सम्पत्ति से से काटने के प्रश्न पर था।

17. जब हमने अभियोक्ता के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि कोई रिहाई विलेख क्यों नहीं निष्पादित किया गया श्री चंद्रन के बच्चे, अर्थात्, अपीलार्थियों, विद्वान वकील ने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि सेंगलानी चेट्टियार, जाहिरा तौर पर, कानून की अपनी समझ पर आगे बढ़े।

हिंदू अल्पसंख्यक और गारंटी अधिनियम की खंड 8 का प्रभाव

18. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की खंड 8 (1), (2) और (3) (इसके बाद के रूप में संदर्भित) '1956 का अधिनियम'), अन्य बातों के साथ साथ साथ, इस प्रकार है:

"8. प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ।-

- (1) हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक को इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी कार्य करने की शक्ति है जो नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग खंड संपत्ति खंड प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए आवश्यक या उचित और उचित हैं; लेकिन अभिभावक किसी भी मामले में नाबालिग को व्यक्तिगत वाचा द्वारा बाध्य नहीं कर सकता है।
- (2) प्राकृतिक संरक्षक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, -
 - (अ) नाबालिक की अचल सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक या शुल्क, या बिक्री,

- उपहार, विनिमय या अन्यथा हस्तांतरण; या
- (ब) ऐसी सम्पत्ति के किसी भी हिस्से को पांच साल के बाद अधिक की अवधि के लिए या उस तिथि के बाद एक साल के बाद अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर दें जिस दिन नाबालिक को बहुमत प्राप्त होगा.
- (स) उप-खंड (1) या उप-खंड (2) के उल्लंघन में किसी प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल सम्पत्ति का कोई भी निपटान, नाबालिग के कहने पर या उससे दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अमान्य है।"

19. अपीलकर्ता एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के विरुद्ध निषेध पर भरोसा करते हैं, जो नाबालिग को एक व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा बाध्य करता है। उक्त प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, यह सिद्धान्त गुलाम अब्बास (ऊपर) में प्रतिपादित किया गया है लागू नहीं होगा यह तर्क दिया जाता है। हम सोचेंगे कि यह एक विवाद है, जो खंड 8 की उचित व्याख्या पर आधारित नहीं हो सकता है।

20. 1956 के अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ खंड 6, अन्य बातों के साथ-साथ, घोषणा करती है कि पिता और उसके पश्चात माँ, एक लड़के या एक अविवाहित लड़की के मामले में, नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की सम्पत्ति के संबंध में स्वाभाविक संरक्षक होना चाहिए। हालाँकि, नाबालिग यद्यपि सम्पत्ति में संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति में नाबालिग का अविभाजित हित शामिल नहीं होगा। इसके बाद, खंड 8 प्रकट होती है और इसका वर्णन करना अभिप्रेत है प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ। प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ दूसरे शब्दों में, अभिभावक या तो व्यक्ति या नाबालिग की सम्पत्ति या दोनों से संबंधित होता

है। खंड 8 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक अभिभावक को उन सभी कार्यों को करने की शक्ति होगी, जो आवश्यक नाबालिग के संरक्षण या लाभ के लिए आवश्यक या उचित और उचित हैं। इसके बाद, यह है कि कानून-दाता ने अभिभावक को नाबालिग को व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा बाध्य करने से रोक दिया है। संक्षेप में, हमें प्रश्न में शब्दों में अर्थ डालने के लिए, पृष्ठभूमि को नाबालिग के अस्तित्व द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और जिसके पास कुछ संपत्ति का अधिकार है। आदेश यदि, नाबालिग की सम्पत्ति के संबंध में, प्राकृतिक संरक्षकों को एक अनुबंध में प्रवेश करना था, तो यह नाबालिग के लिए प्राकृतिक अभिभावक के विरुद्ध निषेध का आह्वान करने के लिए खुला हो सकता है, जो नाबालिग को एक व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा बाध्य करता है।

21. इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थियों के मामले पर गौर किया जा सकता है। यह उनका मामला है कि श्री चंद्रन, उनके पिता, का स्वयं अभियोग अनुसूची सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। यही कारण है कि श्री सेंगलानी चेट्टायर की अलग सम्पत्ति होने के कारण, श्री चंद्रन का इस पर जन्म से कोई अधिकार नहीं था। उनके पास सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 (ए) के अर्थ के भीतर मात्र एक विशिष्ट उत्तराधिकार था। यह अपीलार्थियों का मामला भी नहीं है कि उनके जन्म के समय या उनके पिता की मृत्यु के समय या 1988 में उनके दादा श्री खंडंगलानी चेट्टायर की मृत्यु के समय भी उनका वादी अनुसूची सम्पत्ति में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। जिस अधिकार का वे शुरुआती बिंदु पर दावा करते हैं, तभी उत्पन्न हो सकता है जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अर्थ में श्री खंडंगलानी चेट्टायर की मृत्यु

पर सम्पत्ति को उनकी अलग सम्पत्ति के रूप में मानने जाय । इसलिए, हम उनके पिता श्री चंद्रन द्वारा वर्ष 1975 में निष्पादित रिहाई विलेख को '1956 अधिनियम' की धारा 8 के अर्थ के मात्रतर एक अनुबंध के रूप में त्यागने में असमर्थ हैं।

22. जहाँ तक अपीलार्थियों के इस तर्क का संबंध है कि अपीलार्थियों को एक स्वतंत्र अधिकार होगा, जब श्री सेंगलानी चेट्टायर की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार खुला है, जब 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता पूर्व मृत बेटे की संतान हैं, अर्थात् श्री चंद्रन, जिनकी मृत्यु 09.12.1978 पर हुई थी, हमारा विचार है कि उक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं है। यह सच है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (ए) से, एक निर्वसीयत पुरुष हिंदू की सम्पत्ति, सबसे पहले, अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट रिश्तेदार होने के नाते, उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। यह सच है कि एक पूर्व मृत पुत्र का पुत्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि श्री सेंगलानी चेट्टायर की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपीलार्थियों के पक्ष में सम्पत्ति में एक अधिकार बनाया गया था, क्योंकि वे पूर्व मृत बेटे की संतानें थीं। यद्यपि जो अवरोध लाता है, वह एक पक्ष को अधिकार स्थापित करने से रोक रहा है, जो बहिष्कार के लिए, उसके पास सम्पत्ति में होगा। इस संबंध में, हम स्पेंसर बोवर और टर्नर द्वारा अभ्यावेदन द्वारा एस्टोपेल पुस्तक में 'प्रतिनिधि की मृत्यु या अक्षमता' (पृष्ठ 125-126) शीर्षक से निम्नलिखित चर्चा को देख सकते हैं:

"प्रतिनिधि की मृत्यु या अक्षमता

128. जिस कार्यवाही में निरोध का प्रश्न उठाया जाता है, उस समय प्रतिनिधि की मृत्यु, या कुल या आंशिक अक्षमता (चाहे दिवालिया, शैशवावस्था, पागलपन, छिपाव, या अन्यथा के कारण) के मामले में, निरोध का दायित्व, आम तौर पर बोलते हुए, उन्हीं नियमों के अनुसार, उन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है, या प्रेषित किया जाता है। और समान शर्तों के अधीन रहते हुए, अभ्यावेदन द्वारा प्राप्त अनुबंध से बचने के लिए कार्यवाही के लिए ऐसे प्रतिनिधि का दायित्व।

जहां अभ्यावेदन की तिथि और निष्कासन की स्थापना की तिथि के बीच प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई है, वहां निष्पादक या प्रशासक, या (भूमि के स्वामित्व और संपत्ति के मामले में) मृतक प्रतिनिधि का उत्तराधिकारी या योजना उसी सीमा तक अभ्यावेदन से बाध्य है जिस सीमा तक अभ्यावेदनकर्ता होता, और उसके संबंध में बहिष्कार के सभी बोझों के लिए सफल होता है, जिसके अधीन, उसकी मृत्यु की तिथि पर, ऐसा प्रतिनिधि था।

23. यह ध्यान दिया जाएगा कि अपीलार्थियों के पिता को, उनके आचरण से, बहिष्कृत किया जा रहा है, जैसा कि पाया गया है हमारे द्वारा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 8 (ए) में घोषित शीर्षक का स्रोत या स्रोत है। दूसरे शब्दों में, यह मात्र श्री चंद्रन और अपीलार्थियों के बीच संबंधों पर आधारित है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 8 (ए) के अधिकार, अपीलार्थियों में अधिकार निहित करने का तात्पर्य है। इसलिए हम सोचेंगे कि अपीलकर्ता भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 (ए) के आधार पर प्रतिबंध के सिद्धान्त के संचालन खंड प्रतिरक्षा का दावा करने की स्थिति में नहीं होंगे। यदि गुलाम

अब्बास (ऊपर) में सिद्धान्त लागू होता है, तो, इस तथ्य के बावजूद कि क्या श्री चंद्रन द्वारा कथित रूप से रिहा किया जाना, केवल एक विशिष्ट उत्तराधिकार या यह उम्मीद थी कि मूल्यवान विचार के लिए अपने अधिकारों को स्थानान्तरित करने/जारी करने में उनका आचरण एक अवरोध को जन्म देगा। प्रतिबंध के प्रभाव को उस व्यक्ति के माध्यम द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा रोका नहीं जा सकता है जिसके आचरण ने प्रतिबंध को उत्पन्न किया है। हम धर्म के आधार पर भेद करने के प्रयास में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। इस तरह के प्रतिबंध का सिद्धान्त बिना भेद के लागू होता है।

24. एकमात्र अग्रेतर विवाद जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह विद्वान वकील श्री जयंत मुथ राज द्वारा उठाया गया। उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए गुलाम अब्बास (ऊपर) में सिद्धान्त उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह उनका मामला है कि उक्त मामले में भाइयों को एक लाभ मिला और उसके बाद उन्होंने उन अधिकारों को छोड़ दिया, जो, जैसा कि पाया गया था, उस समय उनके पास नहीं थे। यद्यपि इस मामले में स्थिति समान नहीं है। हमारा मानना है कि यह तर्क तथ्यों के खेल को नजरअंदाज करता है। बहुमूल्य विचार प्राप्त करने और अपने पिता श्री सेंगलानी चेट्टायर को इस आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देने के बाद कि वह श्री चंद्रन द्वारा सम्पत्ति के संबंध में किसी भी दावे से प्रेतवाधित होने की संभावना के बिना सम्पत्ति से निपटने के लिए स्वतंत्र था, श्री चंद्रन द्वारा विचार की प्राप्ति के बाद एक स्पष्ट अवरोध अस्तित्व में आया। प्रतिबंध श्री चंद्रन या उनके बच्चों द्वारा किए गए किसी भी दावे को बराबरी से खारिज कर देगा, अर्थात् अपीलार्थी।

25. ऐसी परिस्थितियों में, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलें याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी। पार्टियां अपना खर्च खुद वहन करेंगी।

.....जे.
[के. एम. जोसेफ]

.....जे.
[हृषिकेश रॉय]

नई दिल्ली;
तारीख: 25 जनवरी, 2023।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुवाद सुवास टूल की सहायता से किया गया है।

आरती सिंह
दिनांक: 24.08.2023.